के केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जोकि देश भर में एक समान हैं और वे मूल्य जिन पर ये अनाज भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सप्लाई किए जाते हैं, के ब्यौरे दिए गए हैं।

[देखिए परिशिष्ट 263, अनुबंध संख्या 27]

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि खाद्यान्नों की खरीदारी करने पर किए गए प्रति क्विंटल वसूली प्रासंगिक खर्च की दर और वितरण खर्च निम्नानुसार रहा है :—

रुपये/क्विंटल

वर्ष	जिन्स	वसूली प्रासंगिक खर्च	वितरण खर्च
1989-90	गेहूं	45.49	76.33
	चावल	21.57	76.33
1990-91	गेहूं	64.34	87.48
	चावल	31.74	87.48
1991-92	गेहूं	72.43	82.77
	चावल	29.81	82.77

Procurement of wheat

1412. SHRI VIREN J. SHAH : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to reduce the wheat quota through public distribution system (PDS) for major wheat producing states Punjab, Haryana and Uttar Pradesh;

(b) if so, what are the details of the proposals;

(c) whether these states have failed to procure substantially for the central pool commensurate with their projected production ;

(d) if so, what is the procurement quota and expected production of wheat in each State ;

(e) what steps Government propose to take to enhance the procurement of wheat for the central pool; and

(f) what special incentive Government propose to give to farmers in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) and (b) Allotments of wheat are made to the States and Union Territories every month based on various. factors, the availability of stocks in the Central Pool being a major consideration.

(c) and (d) The FCI, alongwith the Slalc procuring agencies, havcPprocured the following quantities of wheat in these States till 4-5-1992 in the current rabi marketing season 1992-93 :—

(in lakh tonnes)

States	Projected production for 1991-92 crop year	Qty. procured as on 4-5-1992
Punjab . .	122.00	25.52
Haryana . .	65.50	8.66
U.P. . . .	193.00	1.18
TOTAL .		35.36

The procurement of wheat being based on minimum price support operations, on voluntary basis, no procurement quota can really be fixed.

(e) and (f) Besides other steps being taken to maximise procurement of wheat for Central Pool under price support scheme, the Government has announced a bonus of Rs. 25 per quintal over and above the minimum support price of wheat payable to the farmers for sale of wheat to FCI/its agencies during the period from 1st April, to 31st May, 1902. In addition to this, a bonus of Rs. 5 per quintal has been declared by the Goverement of Punjab and Haryana and Rs. 25 per quintal by Madhya Pradesh Government.

खाद्यान्नों की जमाखोरी

1413. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों की बड़े पैमाने पर जमाखोरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने जमाखोरी के कितने मामले पकड़े हैं और उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष कितने मूल्य को खाद्यान्न जब्त किया गया, इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में जमाखोरों के विरुद्ध छापे मारे जाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं जो खाद्यान्नों कीजमाखोरी करने और खाद्यान्नों के व्यापार में अन्य कदाचार करने में लिप्त पाए गए। एक विवरण संलग्नहै (नीचे देखिए) जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान जमाखोरी के पकड़े गए मामलों की संख्या और जब्त किए गए जमाशुदा खाद्यान्नों का कुल मूल्य दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों की 7-2-1992 को पुनः लिखा गया है जिसमें प्रभावकारी जमाखोरी निरोधी उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1989, 1990 और 1991 के दौरान जमाखोरी के पकड़े गए मामलों की संख्या और जब्त किए गए जमाशुदा खाद्यान्नों के मूल्य का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित प्रदेश	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं०	जिन पर मुकदमा चलाया गया, उनकी संख्या	दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए खाद्यान्नों का मूल्य
1	2	3	4	5
				(लाख रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	4020	108	21	861.26
असम	20	80	14	0.28
अरुणाचल प्रदेश	--	--	---	—
बिहार	429	441	—	276.49
गुजरात	85	98	11	304.50
गोआ	7	6	--	2.96
हरियाणा	284	70	—	643
हिमाचल प्रदेश	2	8	1	0.19
जम्मू तथा कश्मीर	441	142	5	1.72